

डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022

प्रलिमिस के लिये:

डिजिटल इंडिया भाषनी, आरटफिशियल इंटेलजिंस।

मेन्स के लिये:

भारत का डिजिटल इंडिया वज़िन, प्रौद्योगिकी मशिन, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, आरटफिशियल इंटेलजिंस, डिजिटल गवर्नमेंट।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम** के तहत डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य **ब्रूहापार करने में सुगमता** को बढ़ावा देना और जीवन को आसान बनाना है।

- विषय: 'नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा'
 - देश को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलना।
- कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी तक पहुँच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने के लिये सेवा वितरण को सुव्यवस्थिति करने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहलों की शुरुआत की।

डिजिटल पहल:

- डिजिटल इंडिया भाषनी:
 - डिजिटल इंडिया भाषनी भारत का **आरटफिशियल इंटेलजिंस (AI)** के नेतृत्व वाला भाषा अनुवाद मंच है।
 - भाषनी प्लेटफॉर्म आरटफिशियल इंटेलजिंस (AI) और **प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP)** संसाधनों को **MSME (मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम)**, स्टार्टअप एवं व्यक्तिगत इनोवेटरस को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराएगा।
- डिजिटल इंडिया जेनेसिस (GENESIS):
 - डिजिटल इंडिया जेनेसिस 'जेन-नेक्स्ट सोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स' भारत के टथिर- II और टथिर- III शहरों में सफल स्टार्टअप की खोज, समर्थन, विकास और सफल बनाने हेतु एक राष्ट्रीय गहन-तकनीकी स्टार्टअप मंच है।
- माय स्कीम :
 - यह सरकारी योजनाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करने वाला एक सर्व और डिस्कवरी मंच है।
 - इसका उद्देश्य वन-स्टॉप सर्व और डिस्कवरी पोर्टल को प्रस्तुत करना है, जहाँ उपयोगकर्ता उन योजनाओं को खोज सकते हैं जिनके लिये वे पातर हैं।
- मेरी पहचान:
 - यह एक नागरिक लॉगनि के लिये राष्ट्रीय एकल साइन ऑन (NSSO) है।
 - यह एक प्रयोक्ता प्रमाणीकरण सेवा है जिसमें क्रेडेंशियल्स का एक एकल समुच्चय एकाधिकी ऑनलाइन अनुप्रयोगों या सेवाओं तक पहुँच प्रदान करता है।
- चपिस स्टार्टअप (C2S) कार्यक्रम:
 - C2S कार्यक्रम का उद्देश्य बैचलर, परास्नातक और अनुसंधान संतरों पर सेमीकंडक्टर चपिस के डिजिइन के क्षेत्र में विशेष जनशक्ति को प्रशिक्षित करना है तथा देश में अर्द्धचालक डिजिइन में शामलि स्टार्टअप के विकास के लिये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है।
 - यह संगठनात्मक संतर पर सलाह देने की पेशकश करता है और संस्थानों को डिजिइन के लिये अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराता है।
- इंडिया स्टैक ग्लोबल:
 - यह आधार, यूपीआई (यूनिफिल एमेंट इंटरफेस), डिजिलॉकर, काउइन वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म, गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस, दीक्षा प्लेटफॉर्म और आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मशिन जैसी इंडिया स्टैक के तहत कार्यान्वयन प्रमुख परियोजनाओं का वैश्विक भंडार है।
 - यह भारत को जनसंख्या संतर पर डिजिटल परिवर्तन परियोजनाओं के नियमान के नेता के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम:

■ परचियः

- इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था।
- इस कार्यक्रम को भारतनेट, मेक इन इंडिया, स्टारटअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया, औद्योगिक गलियारों आदि जैसी कई महत्त्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के लिये सक्षम किया गया है।

■ विजिन कषेत्रः

- प्रत्येक नागरिक हेतु डिजिटल बुनियादी ढाँचा।
- मांग आधारत शासन और सेवाएँ।
- नागरिकों का डिजिटल सशक्तीकरण।

■ उद्देश्यः

- भारत के जज्ञान को भविष्य के लिये तैयार करना।
- परविरतनकारी होने के लिये IT (भारतीय प्रतिभा) + आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) = आईटी (इंडिया टूमॉरो) को महसूस करना है।
- परविरतन को सक्षम करने के लिये प्रौद्योगिकी को केंद्रीय बनाना।
- कई विभागों को कवर करने वाला एक अम्बरेला कार्यक्रम-

Nine Pillars of Digital India

• TARGETS • COST

1 Broadband Highways
Broadband in 2.5 lakh gram panchayats by Dec 2016; Virtual network operators and smart buildings in cities; National Information Infrastructure by March 2017
₹ 47,686 cr

5 E-Kranti - Electronic Delivery of Services
E-education, broadband, free WiFi, online courses. * E-healthcare, online consultation/records/supply. Full coverage in three years; online cash, load, information for farmers, financial inclusion e-courts, e-police, e-prosecution

7 Electronics Manufacturing – Target Net Zero Imports
Focus on semi-conductor fabrication plants, fabless design, set-top boxes, VSATs, mobiles, consumer & medical electronics, smart energy meters, smart cards, micro-ATMs

2 Universal Mobile Access
Cover rest of 42,300 villages by FY18
₹ 16,000 cr

3 Public Internet Access Programme
Common Service Centres in 2.5 lakh villages by March 2017; 15 lakh post offices to offer multiple services
₹ 4750 cr

6 Information for All
Online hosting of information & documents; Govt engages via social media. Little addition resources needed

8 IT for Jobs
Train 1 crore people in towns/villages in five years (new); three lakh agents to run viable businesses delivering IT services (ongoing); five lakh rural IT workforce in 5 years; BPO in every NE state
₹ 200 cr

4 E-Governance: Reforming Govt through Technology
Simplify forms, create online repositories for school certificates, IDs; integration of services and platforms (Aadhaar, payment Gateway); automate govt workflow; redress grievances

9 Early Harvest Programmes
Biometric attendance by Oct; WiFi in all varsities; secure govt email hotspots in cities with pop > 1 million/tourist centres; ebooks; SMS-based disaster alerts weather info
₹ 900 cr



डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की उपलब्धियाँ :

- वर्ष 2014 से 23 लाख करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण या DBT के माध्यम से लाभारथियों को हस्तांतरण किये गए हैं।
 - आधार, UPI, कोवनि और डिजिलिंकर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाओं ने "ईज़ज़ ऑफ लिविंग" में योगदान दिया है क्योंकि इससे नागरिकों को बना सरकारी कारबालयों या बचौलियों के पास गए ऑनलाइन सेवाएँ मिलती हैं।
- डिजिटल इंडिया ने सरकार को नागरिकों के दरवाज़े और फोन (Doorsteps and Phones) तक पहुँचा दिया है। 1.25 लाख से अधिक सरकारी सेंटर (CSC) और ग्रामीण स्टोर अब ई-कॉमरेस को ग्रामीण भारत में ले जा रहे हैं।
 - इसी प्रकार ग्रामीण संपत्तियों के लिये संपत्ति के दस्तावेज़ज़ प्रौद्योगिकी के उपयोग से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
- वन नेशन वन राशन कारड (ONORC) की मदद से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों हेतु मुफ्त राशन सुनिश्चित किया गया।
- Co-Win प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत ने विश्व का सबसे बड़ा और सबसे कुशल कोविड टीकाकरण एवं कोविडि राहत कार्यक्रम चलाया है।

आगे की राह

- भारत की डिजिटल क्रांतिभारत और उसकी अर्थव्यवस्था के लिये एक आदर्श बदलाव का कारण बनेगी। सार्वजनिक और निजी भागीदारी, अनुकूल सरकारी नीतियों, नवोन्मेषी सुधारों, जनसांख्यिकीय लाभ, बढ़ती आय व भारत की स्टारटअप संस्कृति के उदय की मदद से भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था बन सकता है।
- डिजिटल क्रांति ने बदलते समय के प्रति पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था को लचीला बनने में मदद की है। भविष्य में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था से भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।

सरोतः पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/digital-india-week-2022>

